

आरोप

दस्तावेज पूरे, फिर भी एक घंटा रोके रखा, पैसे की मांग का सनसनीखेज आरोप

बच्चों से भरी स्कूल बस ‘थाने में कैद’



डिंडौरी, नवभारत। यातायात विभाग के कर्मियों के 500 का दम 'मामला अभी थमा भी नहीं था कि गुरुवार के दिन कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय में हुई शिकायत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए यातायात विभाग को एक बार पुनः

सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल बुधवार का दिन सेंट एंजेल हायर सेकेडरी पब्लिक स्कूल की स्कूल बस (क्रमांक एमपी 52 डीए 0216) को पुराने यातायात चौक पर रोककर बच्चों सहित यातायात थाने में खड़ा करा दिया गया। आरोप है कि बस के बावजूद दस्तावेज पूरे होने के साथजूद करीब आधे घंटे तक 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को वाहन सहित अवैधानिक रूप से रोककर रखा गया था।

बुधवार दोपहर 2 बजे छुट्टी के बाद बस बच्चों को पुलिस लाइन क्षेत्र छोड़ने जा रही थी। तभी यातायात कर्मी ने बस रोक ली। चालक द्वारा दस्तावेज दिखाने की बात कहने के बावजूद बस को सीधे थाने ले जाकर खड़ा करा दिया गया। इस दौरान छोटे-छोटे

बच्चे बस में ही बैठे रहे—भूखे, प्यासे और परेशान।

कार्यवाही पर सवाल

बताया गया है कि वाहन के सभी कागजात वैध थे और डिजिटल रूप में उपलब्ध भी। इसके बावजूद जबी जैसी कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नियम पालन के नाम पर बच्चों को थाने में रोकना जायज है।

धमकाया भी गया

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि यातायात कर्मियों द्वारा पैसे की मांग की गई और कथित तौर पर कहा गया— 'हमें भी ऊपर देना पड़ता है।' जब बस संचालक ने पैसे देने से इनकार किया तो रोजाना इसी तरह वाहन खड़ा करने की धमकी दी गई।

अभिभावकों का फूटा गुस्सा

जब बच्चे तय समय पर घर नहीं पहुंच गए। भीड़ बढ़ने के बाद बस को छोड़ा गया। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में आक्रोश और चर्चा को जन्म दे दिया है। वाहन चालक ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर डिंडौरी को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी लाइली रेंज, प्रभारी मंत्री एवं भाजपा जिला अध्यक्ष को भी भेजी गई है।

दस्तावेज पूरे थे तो जल्दी क्यों

बच्चों को थाने में रोकना क्या संवेदनशीलता है? क्या वाकई

‘ऊपर तक’ पैसा पहुंचाने की मजबूरी है? डिंडौरी की सड़कों पर अब चर्चा यही है क्या कानून का पालन हो रहा है, या दबाव की राजनीति? प्रशासन की चुप्पी के बीच यह मामला अब शहर की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुका है। निगाहें अब जांच और कार्रवाई पर टिकी हैं।

इनका कहना है

इनका कहना है -- फिलहाल तो मैं अभी बाहर हूं, लेकिन मामला मेरे संज्ञान में आज ही आया है, जिस पर हमारी समिति द्वारा निर्णय ले उचित कार्यवाही की जायेगी।

माधुरी बिलैया अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड

परीक्षा आज और रोक दिए प्रवेश पत्र

► **अभिभावकों ने सरस्वती विद्यालय पर लगाया मनमानी का आरोप**

नवभारत, उमरिया। बिरसिंहपुर पाली स्थित सरस्वती विद्यालय एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने से ठीक पहले विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई छात्र-छात्राओं के प्रवेश पत्र रोक दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 20 फरवरी से परीक्षा शुरू होनी है, लेकिन बच्चों को अब तक प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में गहरी चिंता और असंतोष व्याप्त है।

अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन फीस वसूली में तो सख्ती दिखाता है, लेकिन छात्रों के भविष्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाही बरत रहा है। प्रवेश पत्र न

मिलने से बच्चों में मानसिक तनाव की स्थिति बन गई है। वे इस असमंजस में हैं कि परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं। पूरे सत्र की मेहनत दांव पर लगने की आशंका से छात्र-छात्राएं भयभीत हैं।

ज्ञातव्य हो कि विद्यालय की कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। शिक्षक के मंदिर कहे जाने वाले संस्थान में ऐसे आयोजन होने से अभिभावकों ने तब भी आपत्ति दर्ज कराई थी। जनचर्चा यह भी है कि जहां एक ओर विद्यार्थियों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जाता है वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता। सूत्रों के अनुसार कई शिक्षकों का 6 से 8 माह तक वेतन लंबित रहने की बात सामने आई है। प्राचार्य और कर्मचारियों के बीच आए दिन कहासुनी की खबरें भी माहौल को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं।

आधार मशीन खराब होने से हितग्राही परेशान

चिल्हारी, उमरिया। जिले के मानपुर तहसील अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र मानपुर में पहले आधार मशीन चालू था जिससे लोक सेवा केंद्र में आने वाले आवेदकों सुविधा प्राप्त हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में आधार मशीन एक साल से बंद होने के कारण लोगों को आधार कार्ड बनवानी एवं गलती सुधरवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जब इस विषय में लोक सेवा केन्द्र के कर्मचारियों से पूछा जाता है तो उनके द्वारा बोला जाता है कि आज चालू हो जाएगा, आज दिनांक तक मशीन नहीं सुधरने से आवेदक परेशान हो रहे हैं। हितग्राहियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द आधार मशीन सुधरवाकर सेवा बहाल की जाए।

डिवाइडर निर्माण में मनमानी का आरोप

► **पूर्व अध्यक्ष ने सीएमओ को सीधा ज्ञापन, सीएमओ ने झाड़ा पल्ला**

शहपुरा, नवभारत। शहपुरा नगर में चल रहे डिवाइडर निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने निर्माण कार्य में कथित मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) को ज्ञापन सौंपा। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पूर्व पार्षद नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया।

पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता का कहना है कि नगर में चल रहे डिवाइडर निर्माण कार्य में गुणवत्ता और मानकों की अनेदखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में न तो निर्धारित मापदंडों का पालन हो रहा है और न ही तकनीकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। इससे भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है और शासकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मानकों के आधार पर डिवाइडर का हो निर्माण—ज्ञापन में उन्होंने उल्लेख किया कि डिवाइडर की ऊंचाई, चौड़ाई और



निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी निर्माण कार्य की धीमी गति और असमान सतह को लेकर आपत्ति जताई है। राजेश गुप्ता ने कहा कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कार्य अधूरा और त्रुटिपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदार को खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि निर्माण कार्य को पारदर्शी तरीके से कराया जाए और समय-समय पर गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

नगर के हित में किया जाएगा आंदोलन—पूर्व नगर पंचायत

अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि नगर के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जनता के टैक्स के पैसों से होने वाले निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ मिलकर आगे की समस्या लंबित है तो वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ताकि मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। संस्था ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक यह सूचना पहुंचाने का आग्रह किया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस बैठक का लाभ उठा सकें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रसूति वार्ड में घूम रहे आवारा कुत्ते

अमरपुर, नवभारत। जिले कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं जिनकी देखरेख करने वाले जिम्मेदार ही लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र का आलम यह है कि सुरक्षित वार्डों में आवारा कुत्ते घुस रहे हैं जो अस्पताल में अपना इलाज करने पहुंचने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों सहित शिशुओं के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं लेकिन शायद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को इस मामले से कोई सरोकार नहीं है।

इसका जीता-जागता उदाहरण तस्वीरों को देखकर देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने एवं बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए एक ओर सरकार सुरक्षित प्रसव और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करती है लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों के हालात इन सबसे विपरीत नजर आ रहे हैं मामला जिले के अमरपुर जनपद मुख्यालय स्थित



सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई तस्वीरें व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही हैं। अमरपुर जनपद मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है जहां बीती रात प्रसूति वार्ड में एक आवारा कुत्ता खुलेआम घूमता नजर आया है। चौकाने वाली बात यह रही कि कुत्ता नवजात शिशुओं के पलंगों के आसपास मंडरता दिखा जिससे संक्रमण और किसी अनहोनी का गंभीर खतरा पैदा हो गया।अस्पताल परिसर में न तो सुरक्षा के इंतजाम

दिखाई दिए और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद रहा। परिजनों ने जब ड्यूटी स्टाफ को सूचना दी तो भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपुर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। अंततः परिजनों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिसके बाद यह लापरवाही उजागर हुई। लोगों का कहना है कि जब प्रसूति वार्ड ही सुरक्षित नहीं है, तो आम मरीजों की सुरक्षा की क्या

गारंटी दी जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले जिला चिकित्सालय और मेहदवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिम्मेदारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई न होने का ही परिणाम है जो अमरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। अब सवाल यह है कि प्रशासन इस गंभीर चूक पर क्या कार्रवाई करता है, क्या जिम्मेदारों पर जवाबदेही तय होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

► **शासकीय आदर्श महाविद्यालय डिंडौरी में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन**

डिंडौरी, नवभारत। शासकीय आदर्श महाविद्यालय डिंडौरी में 17 एवं 18 फरवरी 2026 को ‘भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन’ विषय पर दो दिवसीय सत्रांत सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीयता, माँ सरस्वती पूजन एवं माँ नर्मदा वंदन के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में शाहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुवें, जिला कलेक्टर अंजू पवन भटौरिया, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. सुरेंद्र सिंह परिहार, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुशील कुमार दुबे,

खराब परिणाम व प्राध्यापकों की कमी पर फूटा आक्रोश

► **छात्रों के भविष्य पर संकट को लेकर एनएसयूआई ने कलेक्टर को सीधा ज्ञापन**

नवभारत, उमरिया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन उमरिया ने जिले के समस्त शासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में व्याप्त शैक्षणिक अव्यवस्थाओं, परीक्षा परिणामों में गंभीर त्रुटियों एवं रिक्त प्राध्यापक पदों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा अध्यक्ष मो. असलम शेर के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र-छात्राओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि शासकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से विभिन्न विषयों में नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। कई विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, जिसका सीधा असर परीक्षा परिणामों पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में



बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, जिससे छात्र समुदाय में भारी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। एनएसयूआई द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय सहित जिले के अन्य महाविद्यालयों में कई विषयों में प्राध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। छात्रों को न तो नियमित मार्गदर्शन मिल पा रहा है और न ही पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो पा रहा है। छात्रों का आरोप है कि कक्षाएं नियमित नहीं लग रहीं। एवं कई कक्षाएं ऐसी भी हैं जिनमें प्राध्यापक ही नहीं हैं। परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया

में गंभीर त्रुटियां हुई हैं। कई मेधावी छात्र भी अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए हैं। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है। एनएसयूआई ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा परीक्षा परिणामों की समीक्षा कर त्रुटियों को तत्काल सुधारा जाए। जिला अध्यक्ष मो. असलम शेर ने प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तत्काल रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होती है तो एनएसयूआई छात्रहित में चरणबद्ध आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

दिया बांसुरी का ऑर्डर और लग गई ढाई लाख की चपत

► **रिटायर्ड शिक्षक हुआ साइबर ठगी का शिकार**

नवभारत, उमरिया। जिले के नौरोजाबाद में एक रिटायर्ड शिक्षक के साथ ऑनलाइन ठगी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर साइबर अपराधियों की चालाकी को उजागर कर दिया। सीता के शौक में मंगाई गई बांसुरी उनके लिए भारी पड़ गई और कुछ ही मिनटों में खाते से ढाई लाख रुपये साफ हो गये। पीड़ित राजाराम चौहान ने चेन्नई की एक कंपनी से चार बांसुरियां ऑनलाइन ऑर्डर की थीं। ऑर्डर के बाद उनके क्रेडिट कार्ड पर एक रसीद और डीटीडीसी का ट्रैकिंग नंबर आया। शुरुआत में सब सामान्य लगा। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने पार्सल की स्थिति जानने के लिए

ट्रैकिंग लिंक खोला, तो उसमें एक मोबाइल नंबर दिखा। पार्सल की जानकारी लेने के लिए उन्होंने उस नंबर पर संपर्क किया।

ऐसे शुरू हुई ठगी की कहानी—फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को कूरियर से जुड़ा बताते हुए कहा कि पार्सल में मोबाइल नंबर गलत दर्ज है। उसे ठीक कराने के नाम पर उसने नया नंबर मांगा और भरोसा दिलाया कि सुधार कर दिया जाएगा। यहीं से ठगी की कहानी शुरू हुई। बातों-बातों में आरोपी ने कहा कि नंबर अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उसने एक लिंक भेजा और उस पर कुछ असें कर देने को कहा। इसके बाद उसने बैंक खाता नंबर और एटीएम कार्ड की 16 अंकों की जानकारी मांगी। इतना ही नहीं, कार्ड के पीछे लिखा सीवीवी नंबर भी पृष्ठ लिया। भरोसे में आए शिक्षक ने सारी

जानकारी दे दी। आरोपी ने आश्चस्त किया कि अब पार्सल समय पर मिल जाएगा।

बैंक से एसएमएस आने के बाद चला—कुछ दिन बाद पार्सल समुचुच पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और उन्होंने उसे प्राप्त भी कर लिया। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन असली झटका तब लगा जब बैंक से फोन आया कि उनके खाते से ढाई लाख निकल चुके हैं और तुरंत एटीएम ब्लाक कराया जाए। बेल्लेस चेक करने पर रकम गायब थी। घबराए परिवार ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। मामला थाना नौरोजाबाद और जिला साइबर सेल तक पहुंचा। जांच में सामने आया कि एटीएम की गोपनीय जानकारी साझा करने से ठगों को खाते तक पहुंच मिल गई।



ग्राम पंचायत छदाकला में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने किया सामुदायिक भवन का भूमिपूजन

नौरोजाबाद। उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत छदाकला में पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ज्ञान सिंह द्वारा कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ सीधे आप लोगों तक पहुंच रहा है उन्होंने चलाई जा रही योजना विकसित भारत जी राम जी का उल्लेख करते हुए कहा की सरकार ने पूर्व से चलाई जा रही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया है जिसमे लोगो को अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मिलेगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह, ग्राम पंचायत की सरपंच रामदुलारी सिंह, समाजसेवी दिलदार सिंह, ब्रजेश मिश्रा, सचिव राजेश सिंह, रोजगार सहायक गोवर्धन यादव सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे।

लोको द्वारा जो मेरा स्वागत किया गया है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद जापित करता हूँ उन्होंने कहा की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आप लोगो के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ सीधे आप लोगों तक पहुंच रहा है उन्होंने चलाई जा रही योजना विकसित भारत जी राम जी का उल्लेख करते हुए कहा की सरकार ने पूर्व से चलाई जा रही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया है जिसमे लोगो को अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मिलेगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह, ग्राम पंचायत की सरपंच रामदुलारी सिंह, समाजसेवी दिलदार सिंह, ब्रजेश मिश्रा, सचिव राजेश सिंह, रोजगार सहायक गोवर्धन यादव सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे।

भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर मंथन

► **शासकीय आदर्श महाविद्यालय डिंडौरी में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन**

डिंडौरी, नवभारत। शासकीय आदर्श महाविद्यालय डिंडौरी में 17 एवं 18 फरवरी 2026 को ‘भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन’ विषय पर दो दिवसीय सत्रांत सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीयता, माँ सरस्वती पूजन एवं माँ नर्मदा वंदन के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में शाहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुवें, जिला कलेक्टर अंजू पवन भटौरिया, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. सुरेंद्र सिंह परिहार, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुशील कुमार दुबे,



मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. ब्रह्मानंद त्रिपाठी सहित अनेक शिक्षाविद उपस्थित रहे।
चार तकनीकी सत्रों में हुआ गंभीर विमर्श
सेमिनार संयोजक डॉ. कल्पना मिश्रा ने विषय प्रवर्तन करते हुए महाविद्यालय का परिचय दिया। वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, मेजर-माइनर प्रणाली, क्रेडिट ट्रांसफर एवं परीक्षा पद्धति जैसे

विंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।छात्र-छात्राओं ने नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्न पूछकर संवादात्मक माहौल बनाया। भारतीय ज्ञान परंपरा, सामाजिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं पर भी सारागर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। प्राचार्य डॉ. अजय कोस्टा ने आधार प्रदर्शन किया। संचालन डॉ. विनीत डांडिया एवं डॉ. अरुका द्वारा किया गया।

परंपरा और आधुनिकता पर संतुलित दृष्टिकोण

दूसरे दिन तकनीकी सत्रों की

